(ख) यदि हां, तो तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की मांगें क्या थीं जिसके कारण उन्हें नियमानुसार कार्य करने के लिये मजबूर होना पड़ा तथा क्या सरकार ने इस आंदोलन को समाप्त करने हेतु इन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से वार्ता की है और यदि हां, तो इस वार्ता का क्या परिणाम निकला है, और

(ग) रिजर्व बैंक के कर्मचारी अपनी मांगों के मामले को लेकर हड़ताल का रास्ता अपना रहे हैं इसे देखते हुये क्या सरकार का विचार बैंकिंग सेवा को आवश्यक सेवा घोषित करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) (क) जी हां।

(ख) कर्मचारियों की मांगें वेतनमानों के संशोधन, महंगाई भत्ते, अन्य भत्तों और सेवा शर्तों में सुधार से संबंधित हैं। समझौता कार्रवाई मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के तत्वावधान में हुई थी। कोई समझौता नहीं हो सका। मुख्य श्रम आयुक्त की असफलता की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने इस विवाद का न्याय निर्णय के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का सौंप दिया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (सेवाये अनिवार्य रखना) अध्यादेश के अधीन जारी किये गये आदेश के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक में हड़ताल प्रतिषिद्ध कर दी गई है।

एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स में वाणिज्यिक विमान चालकों की कमी

891 **श्री अनन्त राम जायसवाल** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में वाणिज्यिक विमान चालकों की अत्यधिक कमी है जिसके परिणामस्वरूप इन दोनों एयर लाइन्स की सेवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां तो 31 दिसम्बर, 1974 से 31 दिसम्बर, 1978 की अवधि के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में पृथक्पृथक कितने वाणिज्यिक विमान चालक कार्य कर रहे थे ,

(ग) वाणिज्यिक विमान चालकों की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की अथवा करने का विचार है , और

(घ) वर्ष 1979-80 में एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स द्वारा पृथक् पृथक कितने अतिरिक्त विमान/एयर बस किराये पर लेने अथवा खरीदने का विचार है और इसके लिये कितने अतिरिक्त विमान चालक चाहियें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) जी नहीं, इंडियन एयरलाइन्स के पास अपने चालू परिचालनों के लिये वाणिज्यिक विमानचालकों की कोई कमी नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को दृष्टि में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1980-81 की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये इंडियन एयरलाइन्स ने प्रशिक्षु विमानचालकों की भर्ती के लिये मार्च, 1979 के दौरान एक विज्ञापन जारी किया है तथा चयन किया जा रहा है।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स वर्ष 1981 तक इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में वृद्धि करने के लिये विमान प्राप्ति कार्यक्रम के अनुसार, इंडियन एयरलाइन्स ने सात बोइंग 737 विमानों (जिनमें नष्ट हुये विमान के बदले में लिये जाने वाला एक विमान भी सम्मिलित है) तथा दो एयरबस ए-300 बी 2 विमानों की खरीद के लिये आदेश दे दिये हैं। 1981 में परिचालनों के लिये अपेक्षित अतिरिक्त विमानचालकों की संख्या लगभग 60 है।

एयर इंडिया

एयर इंडिया ने चार बी 747 विमानों की खरीद के लिए (जिनमें 1-1-78 को दुर्घटना में नष्ट हुये विमान के बदले में लिया जाने वाला एक विमान भी सम्मिलित है) आदेश दे दिये हैं। इन विमानों की डिलीवरी मार्च 1980 तक होनी है।

जहां तक अतिरिक्त विमानचालकों की आवश्यकताओं का संबंध है यह सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जहां तक प्रश्न के भाग (क) से (ग) तक के उत्तर में एयर इंडिया से संबंधित सूचना का संबंध है सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Export of Rice

892 SHRI P RAJAGOPAL NAIDU Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state

(a) whether rice has been exported to other countries this year,

(b) if so, how much, and

(c) from which States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) (a) Yes, Sir.

(b) During 1978-79, 67800 MT of Basmati Rice was exported During April-May 1979 a quantity of 3,952 MT of Basmati Rice was exported 10 000 tonnes of rice other than Basmati have been exported and 30,000 tonnes were contracted for export

(c) Basmati Rice was exported from Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. Rice other than Basmati is exported from Central Stocks, Andhra Pradesh and Tamil Nadu.

Export of Jaggery

893. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the MINISTER OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether Jaggery is being exported to other countries;

(b) if so, to which countries; and

(c) the quantity exported this year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG): (a) Yes, Sir.

(b) Cane jaggery was exported chiefly to Ethopia, Hongkong, Malaysia, Nepal, Singapore, U.K., Yemen Arab Republic during April-September, 1978.

(c) The quantity of jaggery exported during April-September, 1978 was 1200 tonnes. Export figures for the full year have not yet been compiled.

Expors of Sugar

894. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether Government have exported sugar to other countries this year;

(b) if so, how much; and

(c) at what rates it sold sugar to these countires?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG): (a) Yes, Sir.

(b) 4,58,500 tonnes (upto 3-7-79).

(c) The rates have been settled on the basis of average London Daily Price.

Restrictions placed by Reserve Bank in giving loans by Nationalised Banks to Small Scale Industries

895. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank have placed restrictions in giving loans by nationalised banks to small scale industries this year; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Suggestions made by Swarnkars Sangh regarding Gold Policy

896. SHRI S. S. SOMANI: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether any deputation of Swarnkars Sangh have recently met him regarding the Gold Policy Committee and financial matter in view of the failure of the gold auction policy and made certain suggestions; and

(b) if so, details regarding the suggestions and the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): (a) Yes, Sir. Representatives of Akhil Bharatiya Swarnkar Sangh, Delhi recently met the Deputy Prime Minister (Finance).

(b) The Swarnkar Sangh in its Memorandum submitted to the Deputy Prime Minister and Finance Minister have *inter alia* made the following suggestions with regard to the Gold Policy of the Government:

(1) Ornament industry be recognised as a cottage industry;

(2) Export of gold ornaments may be made through a Government agency set up on the lines of the Handicraft Board;

(3) The foreign exchange earned from the export of ornaments may be utilised for importation of gold which may be distributed through the State Bank of India to certify goldsmiths at fixed prices.

(4) The institution of dealers may be abolished.

(5) Certified goldsmiths may be given the sole right to manufacture ornaments.

(6) A certified goldsmith may be permitted to employ another certified goldsmith.